



राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर छत्तीसगढ़



क्र. 2818 / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि / पं.ग्रा.वि.वि / 2021  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 15 / 01 / 2021

अवर सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :- माननीय सांसदों को राज्यहित के मुद्दों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भ :- विभागीय पत्र क्रमांक 3580 / 1837 / 22-1 / 2019 अटल नगर, दिनांक  
30 / 12 / 2020

—000—


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा ऐसे मुद्दे जो केन्द्र शासन में लंबित/विचाराधीन है कि जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने का लेख किया गया है।

2/ मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के अर्धशासकीय पत्र, जो माननीय केन्द्रीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को अंकित है, जिसमें दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर केन्द्र शासन से कार्यवाही लंबित/विचाराधीन है कि जानकारी निम्नानुसार है :-

- प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 52257 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण किया जाना शेष है। इन क्षेत्रों में शौचालय निर्माण हेतु रू. 12000/- की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर रू. 18000/- किया जाना।
- वर्तमान में सामुदायिक शौचालय निर्माण की लागत राशि 03 लाख है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु भी शौचालय निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में यह राशि 05 लाख होना चाहिए।

कृपया स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उपरोक्त 02 बिन्दुओं से माननीय सांसदों को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(इफफत आरा)  
मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अब नहीं तो कब ?

भूपेश बघेल  
मुख्यमंत्री

Bhupesh Baghel  
CHIEF MINISTER



मन्त्रालय, महानदी भवन  
अटल नगर रायपुर, 492002, छत्तीसगढ़  
फोन - 91 (771) 2221000, 2221001  
ई-मेल - emcg@nic.in  
Mantralaya, Mahanadi Bhawan,  
Atal Nagar, Raipur, 492002, Chhattisgarh  
Ph.: +91 (771) 2221000, 2221001  
E-mail - emcg@nic.in  
Do.No. .... Date .....

महोदय -

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही  
किए जाने के संबंध में।

प्रदेश में संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के  
क्रियान्वयन संबंध में आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा कि  
वर्ष 2012-13 के आधारभूत सर्वेक्षण में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों  
में 26.76 लाख परिवार शौचालय विहीन तथा 5.96 लाख  
शौचालय अनुपयोगी/क्षतिग्रस्त रहें हैं।

2/ प्रदेश में लक्षित 26.76 लाख शौचालयों के विरुद्ध  
आधारभूत सर्वेक्षण में बढ़े व छूटे हुए 6.47 लाख परिवार को  
शामिल कर कुल 33.23 लाख शौचालयों को निर्माण हुआ।

3/ अवगत हों कि, प्रदेश में व्यक्तिगत पारिवारिक  
शौचालय निर्माण का लक्ष्य 04 जनवरी, 2018 को पूर्ण हो  
चुका है। इस हेतु कुल 2624.65 करोड़ राशि में से  
केन्द्रांश रु. 1574.79 करोड़ के विरुद्ध रु. 1398.80 करोड़  
राशि 31 मार्च, 2018 तक प्राप्त हुई। शेष केन्द्रांश रु. 175.98  
करोड़ सितंबर, 2018 को जारी की गयी। इस प्रकार  
हितग्राहियों को राशि जारी करने में लगभग 01 वर्ष तक का  
विलंब हुआ, जिससे हितग्राहियों में आक्रोश व्याप्त रहा।

4/ विदित हो कि, प्रदेश के LWE क्षेत्रों में 52257  
व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण किया जाना शेष है।  
इन क्षेत्रों में शौचालय निर्माण हेतु रु.12000/- की प्रोत्साहन  
राशि बढ़ाकर रु. 18000/- किया जाना उपयुक्त होगा।

5/ वर्तमान में सामुदायिक शौचालय निर्माण की लागत  
राशि 02 लाख है। इसके अंतर्गत दिव्यांग जनों एवं तृतीय  
लिंग व्यक्तियों हेतु भी शौचालय निर्माण किया जा रहा है।  
वर्तमान परिस्थितियों में यह राशि 05 लाख होना चाहिए।

DS  
स्वच्छ भारत  
मिशन

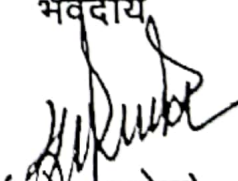
6/ लेख है कि आधारभूत सर्वेक्षण 2012-13 में छूटे हुए 104809 परिवारों के लिए 125.77 करोड़ रूपयों की प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव नवंबर, 2018 में प्रेषित किया गया है, जो आजपर्यन्त अप्राप्त है।

7/ वर्तमान में योजना अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु परिवार संख्या के आधार पर 07 से 20 लाख रूपयों का प्रावधान है, जिसमें गोबर-धन योजना का भी वित्त पोषण किया जाना है। गोबर-धन योजना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत प्रावधानित राशि पर्याप्त नहीं है। फलस्वरूप कार्यों में कठिनाई हो रही है।

8/ इसके अलावा प्रदेश में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कचरे के संग्रहण एवं निपटारे का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस कार्य में संलग्न कर्मचारियों का मनरेगा से मजदूरी भुगतान पर रोक लगा दी गई है, जिससे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अनुरोध के साथ आशा करता हूं कि, उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए राज्य को वांछित धनराशि शीघ्र प्रदाय करने का कष्ट करेंगीं।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,  
  
(भूपेश बघेल)

प्रति,  
सुश्री उमा भारती  
केन्द्रीय मंत्री  
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय  
पर्यावरण भवन CGO Complex  
नई दिल्ली